on the use of 10 pesticides including DDT and BHC.

राष्ट्रीय जल प्रवाह कार्यक्रम

3818. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल प्रवाह कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) कोई राष्ट्रीय जल प्रवाह कार्यक्रम नहीं है। तथापि जल संसाधनों के विकास हेतु सरकार द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए अधिक जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के अन्तरण के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के मध्य अलग-अलग सम्पर्क स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) सरकार ने इन प्रस्तावों को सुनिश्चित करने के लिए 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की। कुल 36 जल अंतरण सम्पर्कों में से, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 17 सम्पर्कों और हिमालयी घटक के अन्तर्गत 19 सम्पर्कों का पता लगाया गया है। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 9 सम्पर्कों का कार्यालय अध्ययन पूरा किया जा चुका है। शेष सम्पर्कों का अध्ययन आठवीं योजना में सम्मिलित किया गया है। प्रायद्वीपीय घटक के 9 सम्पर्कों और हिमालयी घटक के 3 सम्पर्कों का अन्वेषण भी इस अभिकरण के आठवीं योजना कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

[3819. *Transferred to 17th December, 1992.]*

[3820. *Transferred to 16th December, 1992.]*

देश में फलों की पैदावार

3821. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फलों की वार्षिक अनुमानित पैदावार कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने फल उत्पादकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उन्हें लाभकारी मूल्य देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) देश में फलों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन लगभग 280 लाख मी॰ टन है।

(ख) तथा (ग) भारत सरकार के पास किसानों की मदद करने के लिए "एक मण्डी हस्तक्षेप योजना" है, ताकि बागवानी जिन्सों के मूल्यों में गिरावट आने की स्थिति में हस्तक्षेप करके उत्पादों को कम मूल्यों पर बेचने से बचा जा सके। केन्द्रीय नोडल एजेन्सी अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राज्य द्वारा नामित एजेन्सी द्वारा अधिप्राप्त की जाने वाली सीमित मात्रा को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक विनिर्दिष्ट अवधि में निर्धारित मूल्यों पर खरीदने के लिए राज्य सरकारों द्वारा एक प्रस्ताव भेजा जाता है, जिसमें वे यह सहमति भी भेजते हैं कि इस योजना के प्रचालन में यदि कोई हानि होती है तो उसका 50% भार केन्द्र सरकार वहन करेगी।

(ii) वर्ष 1992 के लिए भारत सरकार ने अंगूर एवं किन्नू/माल्टा के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार घोषित की है:

क्रि॰	राज्य	लक्षित मात्रा (मीटरी टन में)	खरीदी गयी मात्रा (मीटरी टन में)	बाजार हस्तक्षेप योजना की दर
1 अंगूर	हरियाणा	2,000	3.75	पिछले 5 वर्षों के
	पंजाब	2,000 (जून 92)	—	औसत एवं 10% बाजार दर

1	2	3	4	5
किनू/माल्टा	पंजाब	10,000	दिसम्बर 1992 से	"ए" श्रेणी 3.25 रु० प्रति
	हरियाणा	2,000	फरवरी 93 के	किलोग्राम "बी" श्रेणी
	उत्तर प्रदेश	2,000	दौरान खरीदे	2.75 रु०
	राजस्थान	500	जाने वाले	प्रतिकिलोग्राम "सी" श्रेणी
				2.25 रु० प्रति कि० ग्रा०

पेड़ों पर छिड़के जाने वाला तेल और कीटनाशी

3822. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेड़ों पर छिड़के जाने वाले तेल और कीटनाशकों तथा जीवनाशकों के बढ़ते हुए मूल्य के कारण इन्हें खरीदना मुश्किल ही नहीं, बल्कि असंभव हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों और बागान मालिकों को राहत देने की दृष्टि से सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) तथा (ख) कीटनाशियों तथा कृमि-नाशियों के औसत मूल्यों में कोई असामान्य वृद्धि देखने में नहीं आई है। तथापि 1992 के दौरान ट्री स्प्रे आयल के मूल्य लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़े। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को, कीटनाशियों पर सबसिडी उपलब्ध है।

Registration of Firms under Insecticides Act

3823. SHRI G.Y. KRISHNAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that NEEM based Insecticides are more effective to protect foodgrains and Crops from Insects and pests, are environmental friendly and now world recognise its effectiveness and having outstanding scope of raw-materials in the country, but Central Insecticide Board, Registration Committee and other concerned authorities and departments are not giving proper attention for its publicity, if so, what are the details thereof;

(b) what are Insecticides, Fungicides, Herbisides Technical and their formulations which are being granted registration under section 9(4) of the Insecticides Act, 1968;

(c) what are the names of the parties/firms with their addresses who have been granted registration under section 9(3B) of the Insecticides Act with date and validity;

(d) the names of the parties, their addresses with products and quantity, who have been allowed Import by the Registration Committee on provisional registrants under the Insecticides Act during the last two years and criteria for allowing of such Import and on whose recommendations, party-wise and product-wise; and

(e) the names of the parties and products whose provisional registrations are pending with the Registration Committee and since when and the quantum of Import requested and criteria for considering such Import requests?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Neem based insecticides have been reported to be effective against number of stored grains and some crop pests. Since Neem based insecticides are environmental friendly, these are considered an important possible input for Integrated Pest Management and the Registration Committee has allowed its